न्यायमूर्ति एस. एस. कांग और मनमोहन सिंह लिहेरहान *समक्ष*

मैसर्स मारुति लिमिटेड (परिसमापन में) और एक अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

मैसर्स पैरी एंड कंपनी लिमिटेड, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 संसद मार्ग, नई दिल्ली।

कंपनी की याचिका सं. 1982 का 82 ।

4 फरवरी, 1988।

कंपनी अधिनियम, *1958* - धारा 446 (2), 458-ए - परिसीमा अधिनियम, 1983 - अनुच्छेद *1958* 137- एस के तहत सीमा को प्राथमिकता दी जाती है। 448(2)- कार्रवाई के कारण का उपार्जन - सीमा की अवधि का प्रारंभ - लेनदेन की अंतिम तारीख से नहीं बल्कि समापन आदेश की तारीख से - एस द्वारा प्रदान किया गया समय। 458-ए को बाहर रखा जाना चाहिए।

यह अधिनिर्धारित किया गया है कि कंपनी/अधिनियम की धारा 448 दावेदार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह दावा करने वालों को प्राथमिकता दे और इसे लागू करे। धारा 446 (2) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ दावे को निर्धारित करने के लिए कंपनी अदालत को विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। यह अधिकार क्षेत्र परिसमापन के आदेश के पारित होने की तारीख से ही शुरू होता है। उक्त तिथि से पहले, कंपनी न्यायालय / न्यायाधीश के पास दावे को निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। दावेदारों के लिए उपाय परिसमापन का आदेश देने की तारीख पर ही उपलब्ध होता है। कार्रवाई का कारण केवल उक्त अधिकार के प्रवर्तन का अधिकार देता है; एचटी। जब उपाय भी उपलब्ध नहीं था, तो कार्रवाई के कारण को इसके प्रवर्तन के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को पढ़ने पर, दावे के लिए कार्रवाई का कारण कंपनी कोर्ट के माध्यम से उपाय का अधिकार केवल उस तारीख को देता है जिस तारीख को दावेदार को उपाय की मांग करने का अधिकार मिलता है, उक्त तारीख समापन आदेश की तारीख है। नतीजतन, धारा 448 (2) के तहत राहत मांगने की कार्रवाई का कारण समापन आदेश होगा।

(पैरा 12)

तीन साल की सीमा की अवधि की गणना करते समय, अधिनियम की धारा 458-ए द्वारा परिकल्पित अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। धारा 458-ए को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कंपनी के समापन की तारीख से समापन आदेश पारित होने की तारीख तक की अवधि, दोनों शामिल हैं, और समापन आदेश की तारीख के तुरंत बाद एक वर्ष की अवधि को परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई तीन साल की अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए।

(पैरा 12)

यह माना गया है कि कंपनी की ओर से अधिनियम की धारा 446 (2) के तहत दावे के लिए आवेदन के लिए सीमा की अवधि, जिसे बंद किया जा रहा है, समापन आदेश की तारीख से शुरू होगी और कंपनी के समापन की तारीख से समापन आदेश की तारीख तक की अवधि होगी। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई तीन वर्ष की अवधि की गणना में समावेशी, और समापन की तारीख के तुरंत बाद एक वर्ष की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

(पैरा 21)

कंपनी अधिनियम, *1956* की धारा *446* के साथ-साथ कंपनी *(*न्यायालय*)* नियमावली, 1959 के नियम *9* के तहत 10,000 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के लिए याचिका। प्रतिवादी से *18,099* रुपये।

इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति एस पी गोयल ने 11 जुलाई, 1986 को की थी और उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि यह मामला कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति एसएस कांग *(*उस समय उनके लॉर्डशिप के रूप में*)* और माननीय न्यायमूर्ति एमएस लिब्रहान की वृहद पीठ ने *4* फरवरी, 1988 के आदेश के तहत इसमें शामिल प्रश्न का निपटारा किया और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया। माननीय न्यायमूर्ति जी आर मजीठिया ने अंततः 18 दिसंबर, 1989 को मामले का फैसला किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से जे. एस. नारंग, वकील।
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल ने पैरवी की।

निर्णय

एम. एस. लिब्रहन, जे.

(1) विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून को फरीदाबाद कोल्ड स्टोरेज एंड अलाइड इंडस्ट्री बनाम फरीदाबाद कोल्ड स्टोरेज एंड एलाइड इंडस्ट्री मामले में रिपोर्ट करने के बाद कानून के निम्नलिखित प्रश्न का उल्लेख किया है।आधिकारिक परिसमापक अमोनिया आपूर्ति निगम प्राइवेट लिमिटेड (1) सही ढंग से नहीं रखा गया है:

> क्या कंपनी अधिनियम की धारा 446 (2) के तहत याचिका पर रोक लगाई गई है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जिस दिन समापन आदेश पारित किया गया था या जिस तारीख को उक्त धारा के तहत याचिका दायर की गई थी?

उपरोक्त प्रश्न को उठाने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स है:

(2) (1978) 48 कॉम्प कैस 432।

मैसर्स मारुति लिमिटेड (परिसमापन में) और एक अन्य वी. मेसर्स पैरी एंड कंपनी लिमिटेड, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 संसद मार्ग, नई दिल्ली (एम. एस. लिब्रहन, जे.)

मैसर्स मारुति लिमिटेड को दिनांक 16 मई, 1977 की याचिका द्वारा बंद करने की मांग की गई थी। एक अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति 22 जुलाई, 1977 को की गई थी, हालांकि समापन के लिए अंतिम आदेश 6 मार्च, 1978 को पारित किया गया था। आधिकारिक परिसमापक ने प्रतिवादी मैसर्स पैरी एंड कंपनी लिमिटेड के खिलाफ 28 अक्टूबर, 1982 को कंपनी अधिनियम की धारा 446 (2) (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत दावा याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि अंतिम लेनदेन 14 जनवरी, 1976 को हुआ था, और खाते में भुगतान 14 अप्रैल को किया गया था। 1978 में कुछ राशि यों को काटने के बाद चेक द्वारा। इन राशियों को कथित रूप से 25 जून, 1979 को स्वीकार किया गया था।

(3) उत्तरदाता ने आग्रह किया; कार्रवाई का कारण 14 जनवरी, 1976 को उत्पन्न हुआ था जब अंतिम लेन-देन हुआ था, अधिनियम की धारा 458 ए का लाभ देने के बाद भी, दावे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। दावे को प्राथमिकता देने की सीमा 14 जनवरी, 1976 को शुरू हुई और इसलिए समापन आदेश पारित होने से पहले ही इसकी वसूली के लिए उपाय पर रोक लगा दी गई। जहां तक कार्रवाई के कारण का संबंध है, कार्रवाई के कारण का संबंध होने के संबंध में कार्रवाई के कारण का कोई संबंध नहीं है। उस अवधि को बाहर करने का कोई कारण नहीं है जिसके लिए समापन के लिए याचिका लंबित रही।

(4) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-कंपनी की उक्त दलीलों को खारिज कर दिया और आग्रह किया कि चूंकि अधिनियम की धारा 446 (2) कंपनी द्वारा और उसके खिलाफ दावे को निर्धारित करने के लिए कंपनी अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करके एक विशेष उपाय प्रदान करती है, इसलिए परिसमापन आदेश पारित करने की तारीख से सीमा शुरू होगी। यह तर्क दिया गया था कि परिसीमा अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जो अधिनियम की धारा 446 (2) के तहत आवेदन पर लागू होता है, यह केवल अवशिष्ट अनुच्छेद 137 है जो कंपनी अदालत में दावे को प्राथमिकता देने के लिए सीमा निर्धारित करेगा। कंपनी अदालत के समक्ष उपाय की मांग करने का अधिकार केवल तभी प्राप्त होता है जब समापन आदेश पारित किया गया हो। समापन आदेश से पहले, कंपनी अदालत / न्यायाधीश के पास किसी भी पक्ष के दावे को निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। धारा 458 ए में नकल की अवधि की गणना के लिए समय को बाहर रखने का प्रावधान है।

(5) अधिनियम की धारा 446 (2) के तहत दावा याचिका को प्राथमिकता देकर उपाय की मांग करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करने के लिए, राहत के लिए कार्रवाई के कारण का कोई असर नहीं पड़ता है। कार्रवाई का कारण राहत का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है। धारा 446 (2) में प्रावधान है

परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में अधिनियम की धारा 446 (2) द्वारा प्रदान किए गए उपाय को लागू करने के लिए सीमा प्रदान की गई है।

अधिनियम की धारा 446 (2) निम्नानुसार है: –

"446(2). वह न्यायालय जो कंपनी को बंद कर रहा है, इस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, निम्नलिखित पर विचार करने या निपटान करने का अधिकार होगा-

(1) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कार्यवाही;

(2) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किया गया कोई भी दावा (भारत में इसकी किसी भी शाखा द्वारा या उसके खिलाफ किए गए दावों सहित)।

(3) कंपनी द्वारा या उसके संबंध में धारा 391 के तहत किया गया कोई भी आवेदन।

(4) प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न, चाहे वह कानून का हो या तथ्य का, जो कंपनी के समापन के दौरान संबंधित या उत्पन्न हो सकता है;

क्या इस तरह का मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई है या शुरू की गई है, या ऐसा दावा या सवाल उठा है या उठता है या इस तरह का आवेदन कंपनी को बंद करने के आदेश से पहले या बाद में किया गया है, या कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 के लागू होने से पहले या बाद में किया गया है।

अधिनियम की अवधारणा 458 क निम्नानुसार है

"458 ए। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) या इस समय लागू किसी अन्य कानून के बावजूद, किसी भी बात के बावजूद, किसी भी कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से किसी भी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करने में, जिसे न्यायालय द्वारा बंद किया जा रहा है, कंपनी के समापन की तारीख से समापन आदेश की तारीख तक की अवधि की गणना करने में। इसमें (दोनों शामिल) और समापन आदेश की तारीख के तुरंत बाद एक साल की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा।

परिसीमा अधिनियम के अवशिष्ट अनुच्छेद 137 में निम्नानुसार है: –

137. कोई अन्य आवेदन जिसके लिए इस प्रभाग में कहीं और परिसीमा की कोई अवधि प्रदान नहीं की गई है।	तीन वर्ष	जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है।

(7) बार में यह विवादित नहीं है कि अधिनियम की धारा 446 (2) के तहत आवेदन, अर्थात, प्रतिवादी के खिलाफ कंपनी द्वारा दावा परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होगा।

(8) किसी क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए ताकि वे दूसरे को निरर्थक न बना दें। विसंगतिपूर्ण स्थिति से बचने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। जिस सामग्री पर क़ानून और उसके प्रावधान बुने गए हैं, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामले को पूरा करने के लिए प्रावधानों की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

(9) यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परिसीमा का कानून एक प्रक्रियात्मक कानून है, यह अधिकार पर रोक नहीं लगाता है बल्कि केवल उपाय पर रोक लगाता है। जब विभिन्न क़ानून एक अधिकार के लिए दो अलग-अलग उपचार प्रदान करते हैं, तो सीमा के संचालन द्वारा एक उपाय की पट्टी स्वचालित रूप से दूसरे को रोक नहीं देगी।

(10) किसी क़ानून की व्याख्या करते समय किसी अधिनियम के शब्दों और उपबंधों को अर्थ देने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उसे क्रियाशील बनाया जा सके, न कि उसे निरर्थक या निरर्थक बनाया जा सके। संविधि के सभी उपबंधों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। परिसीमा अधिनियम के प्रावधान, जो किसी अधिकार को लागू करने के उपाय पर रोक लगाते हैं, को शब्दों के व्याकरणिक अर्थ में सख्ती से माना जाना चाहिए। जब तक क़ानून की भाषा इस तरह से बाध्य न हो, तब तक किसी अधिकार धारक को दंडित करने के प्रभाव को देने के लिए निहितार्थ या अनुमान का कोई अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, वादी को वंचित करने के बजाय उसे उपाय देने का प्रयास किया जाना चाहिए। द्वारा प्रदान किया गया लाभ

सीमा के लिए कोई अपवाद दिया जाना चाहिए। परिसीमा के कानून को इसे प्रतिबंधित करने के बजाय एक उपाय प्रदान करने के पक्ष में उदारतापूर्वक माना जाना चाहिए।

(11) जैसा कि समझा जाता है, कारण या कार्रवाई, दावेदार को उस पार्टी के खिलाफ अपना दावा या अधिकार पेश करने का अधिकार देती है जिसके खिलाफ यह उत्पन्न हुआ है। अधिकार का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि इसके प्रवर्तन के लिए एक उपाय प्रदान नहीं किया जाता है। साधारण नागरिक कानून के तहत, प्रतिवादी के खिलाफ कंपनी को धन के लिए अपने अधिकार / दावे को लागू करने के लिए प्रदान किया गया उपाय वाद के माध्यम से या मध्यस्थता के लिए समझौते के मामले में, मध्यस्थता के माध्यम से है। वाद या मध्यस्थता के उपाय को परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आगे बढ़ाया गया है क्योंकि दावेदार अधिनियम द्वारा विशेष रूप से प्रदान की गई सीमा के भीतर उक्त अधिकार को लागू कर सकता है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए मुकदमे के माध्यम से उपाय की मांग करने के लिए कार्रवाई का कारण उस दिन उत्पन्न माना जाएगा जिस दिन उक्त उपाय को लागू करने का अधिकार उत्पन्न हुआ है, जो निर्विवाद रूप से लेनदेन की अंतिम तारीख है।

(12) अधिनियम की धारा 446 दावेदार को दावे को प्राथमिकता देने और उसे लागू करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करती है। धारा 446 (2) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ दावे को निर्धारित करने के लिए कंपनी न्यायालयों को विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। यह अधिकार क्षेत्र परिसमापन के आदेश के पारित होने की तारीख से ही शुरू होता है। उक्त तिथि से पहले कंपनी न्यायालय/न्यायाधीश के पास दावे का निर्धारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। दावेदार के लिए उपाय परिसमापन का आदेश देने की तारीख पर ही उपलब्ध हो जाता है। कार्रवाई का कारण केवल उक्त अधिकार के प्रवर्तन का अधिकार देता है। कार्रवाई का कारण इसके प्रवर्तन के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है जब उपाय भी उपलब्ध नहीं था। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को पढ़ने पर, दावे के लिए कार्रवाई का कारण कंपनी कोर्ट के माध्यम से उपाय का अधिकार केवल उस तारीख को देता है जिस तारीख को दावेदार को उपाय की मांग करने का अधिकार मिलता है, उक्त तारीख समापन आदेश की तारीख है। नतीजतन, धारा 446 (2) के तहत राहत मांगने की कार्रवाई का कारण समापन आदेश होगा। सीमा निर्धारित करने के लिए, यह वह तारीख होगी जिस पर धारा 446 (2) के तहत याचिका दायर की गई थी। समापन आदेश की तारीख से तीन साल की गणना की जानी चाहिए, जिसके भीतर कंपनी कोर्ट को दावे के माध्यम से याचिका को प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि समापन याचिका पेश किए जाने से पहले या समापन की कार्यवाही के दौरान उत्पन्न कार्रवाई के कारण के आधार पर अधिकार को लागू किया जा सके। धारा 446 (2) के तहत दावे को प्राथमिकता देकर ही उपाय की मांग की गई है। तीन वर्ष की सीमा की उक्त अवधि की गणना करते समय, अधिनियम की धारा 458क द्वारा परिकल्पित अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। धारा 458-ए को पढ़ने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह अवधि

कंपनी के समापन की तारीख से समापन आदेश पारित होने की तारीख तक खर्च किया गया, दोनों शामिल हैं, और समापन आदेश की तारीख के तुरंत बाद एक वर्ष की अवधि को परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई तीन वर्ष की अवधि से बाहर रखना होगा।

(13) री-सेनेरल रोलिंग स्टॉक कंपनी *(2)* में यह देखा गया कि समापन आदेश का प्रभाव कंपनी के पक्ष में परिसीमा के क़ानून के संचालन को रोकना है। आदेश पारित होने के बाद, अदालत में कंपनी के पर्यवेक्षण पद और धारा 446 (2) के तहत याचिका जैसी कार्यवाही से इरोम समापन आदेश पर रोक लग जाती है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। समापन आदेश पारित होने पर एकमात्र। इस प्रकार, दावे का उपाय केवल समापन आदेश पर उत्पन्न होता है।

(14) यदि कार्रवाई के कारण के निर्माण को लेनदेन की अंतिम तिथि के रूप में रखा जाता है और सीमा उक्त तिथि से शुरू होती है, तो दावेदार के लिए उपलब्ध होने से पहले उपाय रोक दिया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप धारा 446 (2) के प्रावधान निरर्थक हो सकते हैं। उक्त व्याख्या कंपनी को कंपनी न्यायालय के समक्ष दावे को प्राथमिकता देने के अधिकार से वंचित करेगी। यह अधिकार उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी किसी व्याख्या की परिकल्पना नहीं की गई है और न ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। कंपनी न्यायालय में जाने का अधिकार केवल समापन आदेश पर प्राप्त होता है। इस प्रकार, कार्रवाई का कारण समापन आदेश की तारीख से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है।

(15) फरीदाबाद कोल्ड स्टोरेज केस (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए पूर्ण पीठ के फैसले में कहा गया है कि धारा 446 (2) द्वारा परिकल्पित दावे का एक अलग अर्थ है। कोई भी दावा केवल कंपनी को उपलब्ध दावे को संदर्भित करता है जब समापन याचिका को प्राथमिकता दी जाती है।

(16) इस न्यायालय की खंडपीठ ने राम चंद पुरी बनाम राम चंद पुरी मामले में यह टिप्पणी की है। लाहौर एनामेलिंग एंड स्टैम्पिंग कंपनी लिमिटेड (3),

> उन्होंने कहा, 'लेनदार सिविल कोर्ट में अपने उपाय को आगे बढ़ाने के लिए जोखिम उठा सकता है या समापन कार्यवाही के फैसले का इंतजार कर सकता है। वह खुद से अच्छी तरह से कह सकता है कि अगर

(2) 1872 VII CH. अपील 646.
(3) ए.आई.आर. 1961 पंजाब 84.

समापन का आदेश दिया जाने वाला है, सिविल कोर्ट में एक उपाय को आगे बढ़ाने के लिए उसकी ओर से समय और धन की अधिक बर्बादी नहीं होगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी हो सकती है कि कानून की अदालत में सामान्य उपाय को आगे बढ़ाना अनुचित हो सकता है और वह कंपनी कोर्ट के फैसले का इंतजार करने और लाभांश का एक हिस्सा प्राप्त करने पर अपना बदलाव करने का फैसला कर सकता है, जो लेनदारों को भुगतान किया जाएगा।

केवल इसलिए कि समापन याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद दीवानी मुकदमा दायर करने पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस उपाय को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर है। कंपनी कानून विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि एक बार समापन आदेश हो जाने के बाद, अदालत की अनुमति के बिना आगे की कोई कार्यवाही या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि समापन आदेश उस दिन का है जब समापन याचिका दायर की गई थी, इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि एक लेनदार अदालत में जल्दी करने और अपने पैसे को जोखिम में डालने के बजाय मामले में अंतिम मुद्दे की प्रतीक्षा करने का हकदार है। एक मायावी उपाय का पीछा करने में समय।

निस्संदेह, यह उपाय संभव नहीं है क्योंकि यदि आदेश दिया जाता है, तो वह उस उपाय के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, और यदि समापन याचिका के लंबित रहने के दौरान वह डिक्री प्राप्त करता है, तो वह किसी भी बेहतर परिस्थितियों में खड़ा नहीं हो सकता है। उनकी स्थिति पहले की तुलना में बेहतर नहीं है, और ऐसा होने के नाते, मुझे सीमा को इस तरह से बढ़ाए जाने में कुछ भी विसंगति नहीं लगती है कि लेनदार अपने दावे को साबित कर सकता है यदि वह यह दिखा सकता है कि जिस दिन समापन के लिए आवेदन किया गया था, उस दिन उसका ऋण प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

हमारे विचार से फरीदाबाद कोल्ड स्टोरेज मामले (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए पूर्ण पीठ के फैसले ने कानून की सही व्याख्या की है और हम उसी के साथ सहमत हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 446 (2) के तहत याचिका के लिए सीमा समापन आदेश की तारीख से शुरू होती है, और अधिनियम की धारा 458 ए द्वारा प्रदान किए गए समय की अवधि की गणना करते समय को बाहर रखा जाना चाहिए।

17.) दावेदार के विद्वान वकील ने आगे यूनिको ट्रेडिंग एंड चिट फंड्स *(इंडिया)* प्राइवेट लिमिटेड पर भरोसा किया। बहुत। एस. एच. लोहाटी और

मैसर्स मारुति लिमिटेड (परिसमापन में) और एक अन्य वी. मेसर्स पैरी एंड कंपनी लिमिटेड, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 संसद मार्ग, नई दिल्ली (एम. एस. लिब्रहन, जे.)

अन्य (4), और आधिकारिक परिसमापक वी। बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इंजीनियरिंग लिमिटेड (5) यद्यपि उक्त निर्णय सीधे संदर्भित प्रश्न को कवर नहीं करते हैं, फिर भी ये दावेदार द्वारा उठाए गए विवाद का समर्थन करते हैं।

18. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की तुलना में अलग दृष्टिकोण लेने के लिए कोई विपरीत दृष्टिकोण या कारण हमारे ध्यान में नहीं लाया है।

19. अधिनियम की धारा 458-ए सीमा के लिए एक अपवाद प्रदान करती है। यह दो व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करता है। प्रावधान के पीछे की मंशा और तर्क पर तभी गौर किया जा सकता है जब प्रावधान दो व्याख्याओं को स्वीकार करता हो। धारा 458-ए का एक सादा पाठ कंपनी कोर्ट में याचिका को प्राथमिकता देने के लिए परिसीमा अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सीमा का अपवाद प्रदान करता है।

20. यह बालकृष्ण सवलराम, पुजारी वाघमारे और अन्य में देखा गया है। श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य, (6), कि सीमा का कृत्रिम प्रावधान हमेशा तर्क या समानता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। धारा 458-ए द्वारा प्रदान की गई अवधि को गणना सीमा के दौरान बाहर रखा जाना चाहिए। कार्रवाई का कारण समापन आदेश की तारीख पर उत्पन्न माना जाएगा और धारा 458-ए द्वारा प्रदान की गई अवधि का लाभ देते हुए, दावा सीमा के भीतर होगा।

21. पीठ ने कहा, 'हमारी उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर हमारा मानना है कि कंपनी की ओर से अधिनियम की धारा 446 (2) के तहत दावे के लिए आवेदन की सीमा की अवधि, जिसे बंद किया जा रहा है, समापन आदेश की तारीख से शुरू होगी और कंपनी के समापन की तारीख से समापन आदेश की तारीख तक की अवधि होगी। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई तीन साल की अवधि की गणना में शामिल और समापन की तारीख के तुरंत बाद एक वर्ष की अवधि को बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार, प्रश्न का उत्तर उपरोक्त शर्तों में दिया जाता है और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेज दिया जाता है।

आर.एन.आर.

(4) (1982) 52 कॉम्प।
(5) (1982) 52 कॉम्प।
(6) एआईआर 1959 एस.सी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और निष्पादन

और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम